e newsletter
issue 26th & 27th
Nov., 2016

# CMAR

## CITY MANAGERS' ASSOCIATION RAJASTHAN

*Promoting Excellence In City Management...*

# CMAR e-Newsletter Issue 26th & 27th November, 2016

| | |
|---|---|
| Editor in Chief: | **Shri Pawan Arora**<br>(Director cum Joint Secretary, LSGD, GoR) |
| Editorial & Compilation: | **Dr. Himani Tiwari**<br>(Coordinator, CMAR)<br>**Mr. Sharawan Kumar Sejoo**<br>(Research Assistant, CMAR) |
| Digital Typesetting: | **Mr. Arjun Pal**<br>(IT Expert, CMAR) |
| CMAR Team: | **Mr. Sandeep Nama**<br>(Research Investigator, CMAR)<br>**Mr. Sitaram Verma**<br>(Assistant, CMAR) |

**Our sincere thanks to:**

| | |
|---|---|
| Shri M.P. Meena (RAS) | (Add. Director, Directorate of Local Bodies, Rajasthan) |
| Dr. Virendra Singh (RAS) | (Dy. Director (Administration), Directorate of Local Bodies, Rajasthan) |
| Shri Hulas Ray Pawar (R.Ac.S) | (Chief Account Officer, Directorate of Local Bodies, Rajasthan) |
| Shri R.K. Vijayvargia | (Sr. Town Planner, Directorate of Local Bodies, Rajasthan) |
| Shri Brijesh Pareek | (PRO, Directorate of Local Bodies, Rajasthan) |


**For suggestions/feedback please write to:**

City Managers' Association Rajasthan, Room No. 410, Directorate of Local Bodies

G-3 Rajmahal Residency, Near Civil Lines, Railway Crossing, Jaipur - 302015,

Telefax: 0141-2229966, website: www.cmar-india.org, Email: cmar.rajasthan@gmail.com


Electronic version of this newsletter is also available on CMAR's website at: http://cmar-india.org/

# Contents


| | |
|---|---|
| स्वच्छता सर्वेक्षण—2017 की जानकारी देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन | 1 |
| सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 के तहत स्थानीय निकाय विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार समाप्त करने की शपथ ली | 4 |
| मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन | 5 |
| एनर्जी सेविंग परियोजना के तहत प्रदेश को देश में प्रथम स्थान | 8 |
| नगर निगम अजमेर का नावाचार मोबाईल लाईब्रेरी | 9 |
| नवनियुक्त अधिशाषी अधिकारी, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक एवं कनिष्ठ लेखाकारों का प्रशिक्षण प्रारम्भ | 10 |

# स्वच्छता सर्वेक्षण–2017 की जानकारी देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के 500 शहरों (1 लाख और उससे अधिक आबादी वाले) में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान प्रारम्भ होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण–2017 की जानकारी देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में 26 अक्टूबर, 2016 को सम्पन्न हुई।

प्रदेश के पहले खुले में शौच मुक्त डूंगरपुर शहर के निकाय प्रमुख श्री के.के. गुप्ता को कार्यशाला में सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस दौरान पंचायती राज संस्थान सफाई व्यवस्था से जुड़े विभिन्न उपकरणों/वाहनों/साधनों की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।

कार्यशाला के प्रारम्भ में प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग डॉ मनजीत सिंह ने बताया कि जनवरी 2016 में देश के 73 शहरों में स्वच्छता रेटिंग के लिए केन्द्रिय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण–2016 का आयोजन किया था। इसी क्रम में 4 जनवरी, 2017 को देश के 500 शहरों में स्वच्छता रेटिंग के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण–2017 का आयोजन किया जा रहा है। उन्होनें बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण–2017 के बारे में निकाय प्रमुखों एवं अधिकारियों को जानकारी देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होनें बताया कि सर्वेक्षण–2017 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए स्वच्छता मे उनकी भागीदारी एवं जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है साथ ही इस सर्वेक्षण से नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने मे सुधार करना एवं सभी नगरीय निकायों में एक स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा को जागृत करना है।

स्वच्छ भारत मिशन के राष्ट्रीय मिशन निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री प्रवीण प्रकाश ने स्वच्छ सर्वेक्षण–2017 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देश में 4 जनवरी, 2017 से स्वच्छ सर्वेक्षण–2017 प्रारम्भ होगा। उन्होनें बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण–2016 में प्रदेश के तीन शहरों जयपुर की 29वीं रेंकिंग, जोधपुर की 57वीं रेंकिंग एवं कोटा की 58वीं रेंकिंग आयी थी। उन्होनें कहा कि कोई भी शहर तब तक स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता जब तक कि वहॉ की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ न हो। उन्होनें बताया कि सर्वेक्षण का कार्य Quality Council of India

(QCI) के माध्यम से किया जायेगा। इस दौरान सर्वेक्षण में शामिल शहरों में Quality Council of India (QCI) की टीम दो दिवस तक विभिन्न स्थानों का आकस्मिक निरीक्षण करेगी तथा वहॉ की महापौर एवं आयुक्त से भी मिलेगी। उन्होनें सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण घटकों की जानकारी देते हुए बताया कि इस सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण घटक नागरिकों की भागीदारी है। सोशियल मीडिया व अन्य परम्परागत मिडिया चैनलो का भी राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर प्रयोग किया जायेगा। जिसमें जनता को सर्वेक्षण और सर्वेक्षण विधि के बारे में जानकारी दिये जाने के साथ–साथ सर्वेक्षण में उनकी भागीदारी तथा सभी नागरिकों की भागीदारी सुशिचित की जायेगी। सर्वेक्षण में सोशियल मिडिया, दूरभाष, पत्र एवं आपसी बातचीत के माध्यम से आम जनता से संबंधित शहर की सफाई व्यवस्था के संबंध में Quality Council of India (QCI) टीम फीडबैक लेगी। इस दौरान यह देखा जाएगा कि संबंधित नगरीय निकाय द्वारा सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वार्ड में बायोमैट्रिक मशीने लगायी गयी है या नहीं। नगरीय निकाय के पास पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मचारी नियुक्त है या नही। शहर से उत्पादित होने वाले कचरे के उठाने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध है या नहीं साथ ही वाहनों में वाहन ट्रैकिंग सिस्टम GPS लगा है या नहीं। यदि पर्याप्त साधन उपलब्ध है तो जितना कचरा उत्पादित होता है वह पूरा उठता है या नहीं। ठोर–टू–डोर कचरा संग्रहण की सफलता के लिए रेक पिकर्स को चिन्हित कर उन्हें निकाय द्वारा अपने साथ लिया गया है या नहीं। निकाय क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक क्षेत्रों में कचरा पात्र रखें है या नहीं एवं वहां पर दिन में दो बार सफाई होती है या नहीं। स्थानीय निकाय द्वारा डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण के लिए यूजर चार्जेज का कलेक्शन किया जा रहा है या नही। स्थानीय निकाय द्वारा रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश के दिन सफाई व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है या नहीं। नगरीय निकाय क्षेत्र में Construction and demolition waste (CDW) को एकत्रित करने की व्यवस्था है या नहीं। निकाय क्षेत्र में रहने वाले आमजन को सर्वेक्षण–2017 के बारे में

जानकारी है या नहीं साथ ही आमजन को स्वच्छता ऐप के बारे में जानकारी है या नहीं। खुले मे शौच मुक्त नगर बनाने के लिए क्या कार्य निती अपनाई जा रहीं है। उन्होने कार्यशाला में सर्वेक्षण की विधि, सर्वेक्षण प्रक्रिया, परिणाम संकेतकों के बारे में जानकारी दी तथा नगरीय निकाय प्रमुखों एवं अधिकारियों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का भी जवाब दिया।

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने इस अवसर पर कहा कि 2 अक्टूबर, 2014 को देश में स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ हुआ था प्रदेश में मिशन के तहत घरेलू शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के साथ–साथ विभिन्न शहरों को खुले में शौच मुक्त

किये जाने का कार्य तेजी से जारी है। इसके अतिरिक्त कचरे के प्रोसेसिंग करने एवं डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण करने के लिए एग्रीमेंट किये गये है।

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के तकनीकी सलाहकार डॉ रमाकान्त ने कार्यशाला में बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत डीजीएस एण्ड डी रेट कांट्रेक्ट के तहत कचरा परिवहन के वाहनों, डम्पर प्लेसर, रोड स्वीपर, डस्टबीन, हैण्डकार्ट, जेसीबी आदि की ऑनलाईन खरीद नगरीय निकाय द्वारा ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से की जा सकती है। इस दौरान स्वायत्त शासन विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री के.के. शर्मा ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भी डीजीएस एण्ड डी रेट कांट्रेक्ट के तहत प्रदेश की सभी नगरीय निकायों को ऑटा हूपर, ऑटो टीपर, सीवर जेटिंग मशीन, जेसीबी, डम्पर, प्लेसर एवं डस्टबीन खरीद की सुविधा उपलब्ध करवाई है।

कार्यशाला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की विषय विशेषज्ञ अल्मित्रा पटेल एवं रागिनी जैन ने विस्तार से जानकारी दी। बीएसएनएल के प्रतिनिधि श्री सुरेश पंचाल ने वाहन जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम की तथा एनबीसीसी इण्डिया के प्रतिनिधि श्री आर.के. धवन ने Construction and demolition waste (CDW) की विस्तार से जानकारी दी। प्रदेश के पहले खुले में शौच मुक्त शहर डूंगरपुर के निकाय प्रमुख श्री के.के. गुप्ता ने डूंगरपुर को खुले में शौच मुक्त किये जाने के दौरान किये गये कार्या की विस्तार से जानकारी दी। नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की पूजा लहरी ने स्वच्छता ऐप की जानकारी चलचित्र के माध्यम से दी। कार्यशाला के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न घटकों पर बनाये गये 10 चलचित्रों को भी प्रदर्शन किया गया।

# सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 के तहत स्थानीय निकाय विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार समाप्त करने की शपथ ली

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग में 04 नवम्बर को प्रातः 11:00 बजे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 के तहत निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोडा के नेतृत्व में सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने की शपथ ली।

इस अवसर पर स्थानीय निकाय निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक श्री एम.पी. मीना, वरिष्ठ नगर नियोजक, श्री राजेन्द्र विजयवर्गीय, मुख्य लेखाधिकारी श्री हुलास राय पवार, मुख्य लेखाधिकारी (आयोजना) श्रीमती मधु राठौड़ सहित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

भ्रष्टाचार को समाप्त करने में आमजन की सहभागीता सुनिश्चित करने के लिये सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 प्रदेश की सभी नगरीय निकायो में 31 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक मनाया जा रहा है।

# मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के प्रभावी क्रियान्वन हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के प्रभावी क्रियान्वन के लिए ''सामाजिक सहभागिता'' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन स्वायत्त शासन भवन के कांफ्रेस हॉल में शुक्रवार को प्रातः 10:00 बजे निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा की अध्यक्षता में किया गया।

इस अवसर पर कार्यशाला में अतिरिक्त निदेशक श्री एम.पी. मीणा, मुख्य अभियन्ता श्री के.के. शर्मा, उपनिदेशक (क्षेत्रीय) श्री विरेन्द्र सिंह, जल ग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग के संचिव श्री अरूण सुराना, भूजल विभाग के श्री जी.पी. शर्मा, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री दीपक दोषी, देव स्थान विभाग के सहायक आयुक्त श्री राजीव पाण्डेय, भूजल विभाग के भूजल वैज्ञानिक श्री जी.पी.शर्मा, तथा सीएमएआर की समन्वयक डॉ हिमानी तिवाड़ी तथा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) एवं विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यशाला में प्रदेश की 66 नगरीय निकायों के विभिन्न Corporate, NGOs व धार्मिक समूह के क्षमता संवर्द्धन एवं विकास योजनाओं की प्रगति एवं सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तार से विचार–विमर्श किया गया।

कार्यशाला के प्रारम्भ में निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री जलस्वावलम्बन योजना का मुख्य उद्देश्य पुराने परम्परागत जलस्त्रोतों जैसे बावड़ी, बड़े तालाब आदि को पुनः चालू करना, मरम्मत करना, जलग्राही बनाना है जिससे इनमें वर्षा के जल का अधिक से अधिक संग्रहण किया जा सके तथा भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा सके एवं इससे घरेलू एवं पेयजल की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। नगरीय निकाय क्षेत्रों में आवश्यक जल हेतु इस प्रकार से पानी के स्त्रोत तैयार हो सकेंगे। उन्होनें कहा कि जलस्त्रोतों की पुनरूद्धार से सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलेगा तथा पर्यावरण एवं शहरी क्षेत्रों में वन विभाग के माध्यम से पौधा रोपण से हरित क्षेत्र बढ़ेगा। जिससे पर्यावरण में व्यापक सुधार हो सकेगा। उन्होनें कहा कि मुख्यमंत्री जलस्वावलम्बन योजना पर 10 दिसम्बर, 2016 से कार्य प्रारम्भ होगा।

निदेशक श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री जलस्वावलम्बन अभियान के तहत प्रदेश के सार्वजनिक भवनों की छतों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से वर्षा जल का संरक्षण भी किया जायेगा। इसके साथ ही 300वर्गगज से अधिक के निजी भवनों में भी वर्षा जल संरक्षण के लिए रूफटॉप

रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाना सुनिश्चित किया गया है। उन्होनें बताया कि प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में तीन वर्ष में जल स्वावलम्बन अभियान के तहत कार्य पूर्ण किये जायेंगे। योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक जिले की दो नगरीय निकाय कुल 66 नगरीय निकयों को वर्ष 2016–17 के लिए चयनित किया गया है। योजना के तहत परम्परागत जल स्त्रोतो को जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कर भूमिगत जल संचय किया जायेगा। उन्होनें कहा कि योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न शहरों द्वारा डीपीआर बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

श्री अरोड़ा ने कार्यशाला में गैर सरकार संगठनों के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अतिरिक्त स्वायत्त शासन विभाग की विभिन्न योजनाओं अमृत, एनयूएलएम, एल,ई.डी. स्वच्छ

भारत मिशन, डोर–टू–डोर कचरा, शहरों को खुले में शौच मुक्त बनाना, संग्रहण, वेंडिग जोन/नॉन वेंडिग जोन, स्मार्टराज आदि योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी एवं योजनाओं में सहयोग के लिए अपील की। उन्होनें बताया कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि 500वर्गगज से बड़े भूखण्डों पर भवन निर्माण दौरान यदि वहां पर 10 या 10 से अधिक मजदूर कार्यरत है तो एक अस्थाई शौचालय बनाना होगा। यदि शौचालय का निर्माण नहीं किया गया तो भवन निर्माण स्वीकृती निरस्त कर दी जायेगी। इसी प्रकार यदि भवन निर्माता द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर बिल्डिंग मैटेरियल/मलबा डाला जाता है तो उसकी भवन निर्माण स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

कार्यशाला में भूजल विभाग के श्री जी.पी. शर्मा ने बताया कि प्रदेश में भूजल भरण 10828. 97एमसीएच है तथा जल का दोहन 14843एमसीएच है। उन्होनें बताया कि वर्ष 1984 में प्रदेश के 12 ब्लॉक अत्यधिक जल दोहन के कारण डार्क जोन थे। जबकि वर्ष 2016 में प्रदेश के 112 ब्लॉक डार्क जोन में है। उन्होनें कहा कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग से ही भूजल का स्तर बढ़ाया जा सकता है। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री दीपक दोषी ने कहा कि आमजन के मध्य पानी को बचाने की जागरूकता आयी है। परन्तु बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की मांग बढ़ी है एवं भूजल स्तर पर गिरावट आयी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वर्षा का स्तर पर न्यूनतम रहता है। ऐसे में रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से ही भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है। उन्होनें बताया कि जयपुर में 72 सरकारी भवनों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार किये गये है।

बैठक में मुख्य अभियन्ता श्री के.के.शर्मा ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत घरेलू शौचालयों, डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण, कचरे की प्रोसेसिंग के लिए प्लान्ट लगाना एवं खुले में शौच मुक्त शहर बनाने जैसी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।

# एनर्जी सेविंग परियोजना के तहत प्रदेश को देश में प्रथम स्थान

## प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर के ''नेशनल एनर्जी कंजरवेशन अवार्ड–2016'' से सम्मानित किया जायेगा

एनर्जी सेविंग परियोजना के तहत देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 14 दिसम्बर को प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर के ''नेशनल एनर्जी कंजरवेशन अवार्ड–2016'' प्रदान करेंगे। अवार्ड स्वायत्त शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि एनर्जी सेविंग परियोजना (एल.ई.डी. लाईट) के तहत देश में 26 नवम्बर, 2016 तक 14 लाख 23 हजार 748 नग लाईटें लगायी गई थी। जिसमें से प्रदेश में सर्वाधिक एल.ई.डी. लाईटें 5 लाख 37 हजार 705 नग लगाई गई है। इस प्रकार से स्ट्रीट लाईट राष्ट्रीय प्रोग्राम ''डैशबोर्ड'' के अनुसार राजस्थान प्रदेश में सर्वाधिक एल.ई.डी. लाईटें लगायी गई है। इसी प्रकार दुसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश तथा तृतीय स्थान पर नई दिल्ली है। डैशबोर्ड पर देश में प्रतिदिन प्रतिराज्य लगने वाली एल.ई.डी. लाईट की संख्या अंकित की जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश द्वारा ऊर्जा बचत के क्षेत्र में किये गये विशेष प्रयास को देखते हुए ''नेशनल एनर्जी कंजरवेशन अवार्ड–2016'' प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर के इस अवार्ड को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 14 दिसम्बर, 2016 को दिल्ली में प्रदान करेंगे। प्रदेश की ओर से यह सम्मान स्वायत्त शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत द्वारा ग्रहण किया जायेगा। चीन की संख्या इंटरनेशनल (आई.एस.ए.) अलाईन्स (आई.एस.एल) द्वारा भी इस प्रोजेक्ट में कार्यरत फर्म सूर्या रोशनी लिमिटेड को भीलवाड़ा में उत्कृष्ठ कार्य करने पर सम्मानित किया जायेगा।

उन्होनें बताया कि एनर्जी सेविंग एल.ई.डी. लाईट परियोजना मार्च 2017 तक प्रदेश में पूर्ण हो जायेगी। परम्परागत सोडियम व ट्यूबलाईटों के स्थानों पर एनर्जी सेविंग की एल.ई.डी. लाईट लगाने से लगभग 55 से 60 प्रतिशत ऊर्जा बचत होगी। प्रदेश में अभी तक 35 शहरी निकायों में एल.ई.डी. लाईट लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिनमें से झालावाड़, माउण्ट आबू, पुष्कर, रतननगर, रतनगढ़, धौलपुर, पाली, उदयपुर, अजमेर, नागौर, आमेट, विद्याविहार, पिलानी, नाथद्वारा, राजसमंद, नवलगढ़, लक्ष्मगढ़, बिसाऊ, डीडवाना, जैसलमेर, सांगोद, कैथून, नीम का थाना, निवाई, जोबनेर, भिवाड़ी, पिड़ावा, निम्बाहेड़ा, किशनगढ़, मकराना, भीलवाड़ा, अकलेरा, चित्तौड़गढ़, रावतभाटा शामिल है। प्रदेश के 48 शहरी निकाय क्षेत्रों में एल.ई.डी. लाईटें लगाने का कार्य तेजी से प्रगति पर है तथा 7 शहरी निकायो में सर्वे का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। तथा 98 शहरी निकाय क्षेत्रों में एल.ई.डी. लाईट लगाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

# नगर निगम अजमेर का नवाचार मोबाईल लाईब्रेरी

नगर निगम अजमेर द्वारा बुक बैंक से साथ ही मोबाईल लाईब्रेरी को भी संचालित किया जा रहा है। जिसमें विभिन्न स्थानों पर प्रत्येक पखवाड़े में एक बार मोबाईल लाईब्रेरी को भेजा रहा है, इस लाईब्रेरी का साप्ताहिक अवकाश बुधवार को रहता है। यहां प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ–साथ विभिन्न प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें भी रखवाई गई हैं जो कि आमजन के साथ छात्र–छात्राओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसी कारण शहर के प्रमुख स्थानों के साथ ही विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में भी इसकी उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। मोबाईल लाईब्रेरी की पहुॅच प्रत्येक व्यक्ति तक हो सके इसके लिए शुल्क को अत्यन्त कम कर 20 रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क रखा है। जिस पर कोई भी व्यक्ति 2 सप्ताह हेतु उपलबध पुस्तकों में अपने मन पसन्द पुस्तक को जारी करवा सकता है। इस मोबाईल लाईब्रेरी में आमजन एवं छात्रों के बैठ कर पड़ने की व्यवस्था है साथ ही तकनीक के साथ हाथ मिलाते हुए ई–रिडिंग हेतु किंडल भी मोबाईल लाईब्रेरी में रखवायें गये है जो कि आमजन को लाईब्रेरी में उपलब्ध होंगे। लाईब्रेरी में सहायता हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर के पास उपलब्ध पुस्तकों की सूची की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध रहती है। मोबाईल लाईब्रेरी की पहल को जिलें में स्थित महाविद्यालयों एवं साहित्यिक संगठनों द्वारा सराहा गया है एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा भी मोबाईल लाईब्रेरी के प्रयास को सम्पूर्ण राज्य में चलाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

# नवनियुक्त अधिशाषी अधिकारी (चतुर्थ), राजस्व अधिकारी (द्वितीय), राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक एवं कनिष्ठ लेखाकारों का प्रशिक्षण प्रारम्भ

अधिशाषी अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी का प्रशिक्षण हरिशचन्द माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में तथा राजस्व निरीक्षक एवं सहायक राजस्व निरीक्षक का प्रशिक्षण क्षेत्रीय केन्द्र हरिशचन्द माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान उदयपुर तथा कनिष्ठ लेखाकार का प्रशिक्षण हरिशचन्द माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, कोटा, जोधपुर, बीकानेर में 21 नवम्बर, 2016 से प्रारम्भ हो गया है।

प्रशिक्षण के प्रथम चरण में फाउण्डेशन कोर्स से सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारी उपलब्ध करवाई गई है तथा अधिशाषी अधिकारी (चतुर्थ) एवं राजस्व अधिकारी (द्वितीय) के लिए प्रशिक्षण के दौरान सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, डेलावास का शैक्षणिक भ्रमण भी करवाया गया।

# Our Partners

National Institute of Urban Affairs

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

ICMA International City/County Management Association

USAEP United States-Asia Environmental Partnership

CMAR

*City Managers' Association Rajasthan, Room No. 410, Directorate of Local Bodies*
*G-3 Rajmahal Residency, Near Civil Lines, Railway Crossing, Jaipur - 302015,*
*Telefax: 0141-2229966*
*website: www.cmar-india.org*
*Email: cmar.rajasthan@gmail.com*

*Electronic version of this newsletter is also available on CMAR's website at: http://cmar-india.org/*